AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

22 से 30 अप्रैल 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- उड़ान (UDAN) का पांचवां दौर
- विश्व पृथ्वी दिवस
- पीएसएलवी-सी55/टेलीओस-2 मिशन
- मेंहगाई राहत कैंप
- एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) का महत्व
- सैन्य अभियानों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया
- एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg,
Agra Road, Jaipur - 302003

Current Affairs 22 April to 30 April

Breifs-

- उड़ान (UDAN) का पांचवां दौर
- सुपरबिट क्या है?
- विश्व पृथ्वी दिवस
- राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस
- पीएसएलवी-सी55/टेलीओस-2 मिशन
- नागास्त्र 1
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस –
- मेंहगाई राहत कैंप'
- 100 फूड स्ट्रीट -
- अभ्यास INIOCHOS-23
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)
- सेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 में प्रमुख निर्णय
- टीईएस मॉडल परिवर्तन
- पैरालंपिक घटनाओं के लिए प्रशिक्षण
- लीड निदेशालय और टेस्ट बेड फॉर्मेशन
- विश्व विकास रिपोर्ट 2023: प्रवासी, शरणार्थी और समाज
- मैच-मोटिव फ्रेमवर्क
- उत्पत्ति और गंतव्य देशों के लिए नीतियां
- जनसंख्या परिवर्तन
- द बिग कैच-अप -
- एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया
- विश्व बौद्धिक संपदा दिवस
- नवीनतम SIPRI रिपोर्ट
- नाटो का रक्षा व्यय लक्ष्य
- रंग घर
- 2023 सूडान संघर्ष

उड़ान (UDAN) का पांचवां दौर

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के पांचवें दौर की शुरुआत की, जिसे उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) के नाम से जाना जाता है। इससे पूरे भारत में दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- उड़ान 5.0 श्रेणी-2 (20-80 सीट) और श्रेणी-3 (>80 सीट) की उड़ानों पर केंद्रित है, जिसमें मूल और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) को बढ़ाकर 600 किमी चरण लंबाई कर दिया गया है।
- केवल एयरलाइनों द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त करने के बाद, एयरलाइंस को दो महीने के भीतर एक कार्य/व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उनकी विमान अधिग्रहण योजना, विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट आदि शामिल हैं।
- एयरलाइंस को एक से अधिक बार एक ही मार्ग से सम्मानित नहीं किया जा सकता है, चाहे अलग-अलग नेटवर्क या एक ही नेटवर्क में।
- यदि औसत त्रैमासिक पीएलएफ लगातार चार तिमाहियों के लिए 75 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो विमुद्रीकरण के मार्ग में शोषण के उदाहरणों को समाप्त करने के लिए विशिष्टता को वापस ले लिया जाएगा।
- एयरलाइंस को रूट दिए जाने के चार महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा।
- इस योजना में हवाईअड्डों की एक सूची शामिल है जो तैयार हैं या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे, जिससे योजना के तहत मार्गों को संचालित करना आसान हो जाएगा।
- एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को रूट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल और प्रोत्साहित किया जाएगा।

उड़ान 5.0: दृष्टि और लाभ

UDAN यात्रियों, एयरलाइनों और कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित विविध हितधारकों के लिए फायदेमंद रहा है। यात्रियों को हवाई संपर्क तक पहुंच प्राप्त हुई है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, और सेवा से वंचित क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए हैं। उड़ान 5.0 हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सस्ती और सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अपनी शुरुआत के बाद से, UDAN कई क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ है जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। योजना का यह नया और मजबूत संस्करण गति को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा, और हमें निकट भविष्य में 1000 मार्गों और 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा।

सुपरबिट क्या है?

SuperBIT एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे आकाशगंगा समूहों के सटीक कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डरहम विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और नासा की संयुक्त

परियोजना के रूप में, SuperBIT का उद्देश्य आकाशगंगा समूहों में डार्क मैटर की उपस्थिति और मात्रा के साथ-साथ ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का पता लगाना है।

समकक्ष उपग्रह की तुलना में, सुपरबीआईटी अपेक्षाकृत सस्ती है, लगभग £4.1मिलियन/$5मिलियन अमरीकी डालर की लागत के साथ। इसकी कम लागत के बावजूद, SuperBIT में निकट-अवरक्त (900 एनएम) से निकट-पराबैंगनी (300 एनएम) तक ऑप्टिकल संवेदनशीलता की एक प्रभावशाली सीमा है। पृथ्वी के वायुमंडल से 33.5 किमी की इसकी अनूठी परिचालन ऊंचाई इसे अंतरिक्ष जैसी प्रदर्शन और स्थितियों को प्राप्त करने की अनुमति देती है।

सुपरबीआईटी का मुख्य उद्देश्य डार्क मैटर, एक अदृश्य और सघन पदार्थ की विशेषताओं का आकलन करना है। जिस तरह से डार्क मैटर प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, उसका अवलोकन करके वैज्ञानिक आकाशगंगा समूहों में इसके वितरण को मैप कर सकते हैं। अपनी पहली उड़ान के दौरान, सुपरबीआईटी यह जांचने का इरादा रखता है कि क्या डार्क मैटर के कण आकाशगंगाओं के समूहों के चारों ओर डार्क मैटर वितरण का नक्शा बनाकर एक दूसरे से टकरा सकते हैं जो अपने पड़ोसी समूहों से टकराने की प्रक्रिया में हैं। SuperBIT डार्क मैटर के वितरण को यह देखकर मैप करता है कि यह प्रकाश के मार्ग को कैसे मोड़ता है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक डार्क मैटर के वितरण का एक नक्शा बना सकते हैं और इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।

एंटीना आकाशगंगा और टारेंटयुला नेबुला

16 अप्रैल, 2023 को इसके हालिया लॉन्च के दौरान ली गई सुपरबिट की पहली छवियों में टारेंटयुला नेबुला और एंटीना आकाशगंगाओं के बीच टकराव शामिल है। टारेंटयुला नेबुला आयनित हाइड्रोजन गैस का एक विशाल तारा-गठन क्षेत्र है, जो बड़े मैगेलैनिक बादल में पृथ्वी से 161,000 प्रकाश-वर्ष स्थित है। क्षेत्र के भीतर चमकीले, नवगठित तारे धूल और गैस के घूमने वाले बादलों से घिरे हुए हैं जो अशांत प्रतीत होते हैं। ऐन्टेना आकाशगंगाएँ, NGC 4038 और NGC 4039, दो बड़ी आकाशगंगाएँ हैं जो 60 मिलियन प्रकाश-वर्ष दूर कोर्वस के दक्षिणी तारामंडल की ओर टकरा रही हैं।

विश्व पृथ्वी दिवस

पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे दुनिया भर के 193 देशों में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, और तब से, यह समितियों और संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के साथ एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

पृथ्वी सप्ताह, हर साल 16 से 22 अप्रैल तक मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस का एक अनौपचारिक विस्तारित उत्सव है। यह पृथ्वी दिवस, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। अर्थ वीक हमारे ग्रह की रक्षा के लिए बातचीत शुरू करने, जागरूकता बढ़ाने और सार्थक कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक साथ आने और पर्यावरणीय स्थिरता के अभियान को आगे बढ़ाने का समय है।

विश्व पृथ्वी दिवस 2023: थीम

विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम "हमारे ग्रह में निवेश करें" है, जो 2022 की थीम की निरंतरता है। यह विषय वैश्विक स्तर पर हमारे ग्रह को बचाने के प्रयासों में निवेश के महत्व पर जोर देता है। पृथ्वी दिवस 2023 थीम के पांच फीचर कार्यक्रम सस्टेनेबल फैशन, द ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप, कैनोपी प्रोजेक्ट, क्लाइमेट एंड एनवायर्नमेंटल लिटरेसी, और फूड एंड एनवायरनमेंट और ग्लोबल अर्थ चैलेंज हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरण के लिए कार्रवाई करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाना है।

पृथ्वी दिवस का इतिहास और महत्व

शांति कार्यकर्ता जॉन मैककोनेल ने 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में पृथ्वी दिवस की संकल्पना की थी। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने के लिए मनाया गया था। 1990 में, विभिन्न आयोजनों और गतिविधियों में 141 देशों की भागीदारी के साथ पृथ्वी दिवस वैश्विक हो गया। 2016 में, पृ

थ्वी दिवस को जलवायु संरक्षण के लिए एक अंतर-सरकारी संधि, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ और अधिक महत्व मिला। 2020 में, पृथ्वी दिवस ने इस वैश्विक आंदोलन के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव और महत्व को प्रदर्शित करते हुए अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई।

राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह देश के विकास में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देता है।

भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में चुना गया था। उन्हें व्यापक रूप से 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में जाना जाता है और भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को एकजुट करने के पटेल के प्रयासों को हर साल इस दिन याद किया जाता है क्योंकि देश भर के सिविल सेवक देश में उनके योगदान का जश्न मनाते हैं।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का इतिहास

पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, 2006 को मनाया गया था। इसे सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान करने और भारत के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सिविल सेवकों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए चुना गया था। यह दिन सार्वजनिक सेवा के महत्व को याद दिलाता है और सिविल सेवकों को प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ जनता की सेवा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का महत्व

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भारत के विकास की दिशा में सिविल सेवकों के प्रयासों को पहचानने और उनकी सराहना करने का दिन है। यह सार्वजनिक सेवा के महत्व की याद दिलाने के रूप में कार्य करता है और लोक सेवकों को समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पीएसएलवी-सी55/टेलीओस-2 मिशन

हाल ही में, ISRO ने सिंगापुर निर्मित दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV-C55/TeLEOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतरिक्ष निर्वात में परीक्षण करने के लिए इस मिशन के हिस्से के रूप में एक कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया था।

TeLEOS-2 और Lumelite-4 सिंगापुर निर्मित दो उपग्रह हैं जिन्हें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) पर लॉन्च किया गया था। TeLEOS-2, 741 किलोग्राम वजनी, सिंगापुर सरकार और सिंगापुर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा विकसित एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूसरी ओर, ल्यूमलाइट-4, सिंगापुर स्थित ST Engineering Geo-Insights Pte Ltd द्वारा विकसित एक छोटा, 16 किलोग्राम का उपग्रह है, जिसका उद्देश्य शहर-राज्य की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है।

पीएसएलवी-सी55 मिशन

पीएसएलवी-सी55 मिशन, जिसके तहत दो उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, एक से अधिक तरीकों से महत्वपूर्ण है। यह वर्ष 2022 के इसरो के पहले वाणिज्यिक मिशन को चिह्नित करता है, और पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) का उपयोग करने वाला इसका पहला मिशन भी है - लॉन्च वाहन का चौथा चरण जिसे वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक प्रायोगिक मंच के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। पीओईएम सात गैर-वियोज्य पेलोड ले जा रहा है, जिसमें नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल (एनजीसी) सिस्टम शामिल है, जिसका उपयोग रवैया स्थिरीकरण के लिए किया जाएगा, और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित स्टारबेरी सेंस पेलोड, जो एक कम लागत वाली डिवाइस है अंतरिक्ष में तारों की स्थिति की सटीक पहचान और माप। पीओईएम द्वारा ले जाए गए अन्य पेलोड में आईआईएसटी से एक ओबीसी पैकेज, पायलट (पीएसएलवी इन ऑर्बिटल ओबीसी और थर्मल्स) शामिल हैं; ARIS-2 (आयनमंडलीय अध्ययन के लिए उन्नत मंदता क्षमता विश्लेषक) IIST से प्रयोग; Bellatrix का HET-आधारित ARKA200 इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम; ध्रुव स्पेस से S- और X- बैंड में DSOL-ट्रांसीवर के साथ DSOD-3U और DSOD-6U डिप्लॉयर यूनिट।

पायलट पेलोड और ARKA200 इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पेलोड

PSLV इन ऑर्बिटल ओबीसी और थर्मल्स (PiLOT) पेलोड का उद्देश्य अंतरिक्ष में ऑन-बोर्ड कंप्यूटर और थर्मल वातावरण का परीक्षण करना है। Bellatrix द्वारा विकसित HET-आधारित ARKA200 इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पेलोड, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जिसका उद्देश्य भविष्य के मिशनों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के प्रदर्शन का परीक्षण करना है।

नागास्त्र 1

भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी नागास्त्र-1 युद्ध सामग्री खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके महत्वपूर्ण प्रगति की है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (ईईएल) द्वारा विकसित, सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी, बैंगलोर से जेड-मोशन के सहयोग से, नागास्त्र -1 भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर है, जो अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए इज़राइल और पोलैंड के प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल गया है।

नागास्त्र -1 एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) है जो उन्नत सुविधाओं जैसे गर्भपात, पुनर्प्राप्ति और पुन: उपयोग क्षमताओं के साथ गोला-बारूद को लूटने के लिए है। इसकी श्रेष्ठ विशेषताएं इसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत देशों द्वारा

विकसित समान प्रणालियों के बीच में खड़ा करती हैं। नागास्त्र-1 भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और 'मेक-इन-इंडिया' पहल के अनुरूप है।

भारत के रक्षा उद्योग की अग्रणी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने भारतीय सेना को नागास्त्र-1 प्रदान करने का ठेका हासिल किया है। गोला-बारूद और रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के लिए कंपनी के प्रयास के परिणामस्वरूप पहले घरेलू लॉटर म्यूनिशन (एलएम) का विकास हुआ है। यह उपलब्धि इकनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (ईईएल) और जेड-मोशन के सहयोग से संभव हुई है।

आपातकालीन खरीद प्रावधान और वितरण समयरेखा

भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रावधानों के तहत नागास्त्र-1 के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे एक वर्ष के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। इन आपातकालीन खरीद सौदों का अधिकतम मूल्य ₹300 करोड़ हो सकता है, जो आपातकालीन स्थितियों में स्वदेशी रक्षा उत्पादों को दी गई तात्कालिकता और प्राथमिकता को दर्शाता है। इस तरह के उपाय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करते हैं।

हथियारबंद ड्रोन के साथ स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देना

सोलर इंडस्ट्रीज ने विभिन्न प्रकार के हथियारयुक्त ड्रोन बनाने का काम किया है, जिनमें नागास्त्र-1 भी शामिल है। ये ड्रोन गुरुत्वाकर्षण ड्रॉप बमों, निर्देशित मिसाइलों या कामिकेज़ मोड का उपयोग करके लक्ष्यों की एक श्रृंखला को बेअसर करने की क्षमता रखते हैं। यह युद्ध मशीनरी के रूप में ड्रोन/यूएवी का उपयोग करने की स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भारतीय सेना द्वारा नागास्त्र-1 का सफल विकास और अधिग्रहण गोला-बारूद और रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सैन्य अभियानों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया

सैन्य अभियानों में एक बल गुणक के रूप में ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता दुनिया भर में प्रदर्शित की गई है। हाल के संघर्ष, जैसे कि सीरिया में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, सऊदी अरब में तेल क्षेत्रों पर हमला, और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष, ने समकालीन युद्ध में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। भारतीय सेना द्वारा नागास्त्र-1 का अधिग्रहण रक्षा प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति और स्वदेशी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस –

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है। यह 1993 में उस दिन को चिह्नित करता है, जब भारत में संवैधानिक स्थिति वाली पंचायती राज व्यवस्था।

पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व की हैं। "पंचायत" शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में हुई है, जहां "पंच" का अर्थ "पांच" है और "आयत" "विधानसभा" का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य काल के दौरान, प्रशासन विकेंद्रीकृत था, और स्थानीय स्वशासन आदर्श था। 1959 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के नेतृत्व में आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू में लागू किया गया था। हालाँकि, यह केवल 1993 में, भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन के साथ, इस प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)

पीआरआई, जो भारत में शासन का तीसरा स्तर है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए जवाबदेह हैं। 73वें संशोधन के तहत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता थी। स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे यह भी गारंटी देते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं और समाज के वंचित वर्ग शामिल हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का महत्व

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अवसर पंचायती राज ढांचे को क्रियान्वित करने में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने और उन क्षेत्रों को पहचानने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह दिन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने में पंचायती राज प्रतिष्ठानों की भूमिका को स्वीकार करता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की थीम

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की थीम "सतत पंचायत: स्वस्थ, पर्याप्त जल, स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण" है। विषय का उद्देश्य स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करके, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने और स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल दोनों तरह के वातावरण की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। यह विषय पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर देता है।

मेंहगाई राहत कैंप'

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 अप्रैल को सांगानेर के महापुरा ग्राम पंचायत में 'मेहंगई राहत शिविर' का उद्घाटन करने वाले हैं। इस साल 30 जून तक चलने वाले इस कैंप का मकसद आम जनता और वंचित वर्ग को बढ़ती कीमतों और महंगाई से राहत दिलाना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेंहगाई राहत शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सशक्त बनाना है। शिविर के माध्यम से सरकार का उद्देश्य आम जनता और वंचित वर्गों को अधिकार, योजना और पात्रता की पूरी जानकारी प्रदान करना है। यह शिविर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने, महंगाई और बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

कल्याणकारी योजनाएँ

मेंहगाई राहत शिविर आम लोगों को 10 जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करेगा। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, भूमिहीन मजदूरों और कृषि पाठ्यक्रम स्नातक बेरोजगार युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करना है। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव, भूमिहीन मजदूरों को मैनुअल कृषि मशीनरी खरीदने के लिए अनुदान और किसानों को कृषि मशीनरी प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

पंजीकरण और शिविर विवरण

राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल होने के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। शिविरों को जिलों के सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगभग 2,000 स्थायी मुद्रास्फीति राहत शिविरों में स्थापित किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के जन आधार कार्ड के माध्यम से अन्य जिलों के शिविरों में भी पंजीयन कराया जा सकता है।

100 फूड स्ट्रीट -

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यटन क्षमता को बढ़ाना भी है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अभिसरण में और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से तकनीकी सहायता के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से खाद्य सड़कों की पहल को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक फूड स्ट्रीट या जिले के लिए ₹1 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता का अनुपात या तो 60:40 या 90:10 होगा, इस आवश्यकता के साथ कि फूड स्ट्रीट मानक ब्रांडिंग के लिए FSSAI के दिशानिर्देशों का पालन करें। एफएसएसएआई परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सड़कें स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

पहल का उद्देश्य और लाभ

फूड स्ट्रीट पहल का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तक आसान पहुंच प्रदान करके, पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के अलावा, पहल के कई अन्य लाभ भी हैं। यह स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करके और पर्यटन क्षमता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह स्थानीय खाद्य व्यवसायों की स्वच्छता विश्वसनीयता में सुधार करेगा, जिससे "सही खाओ अभियान" और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना से जुड़ी अन्य पहलें

वित्तीय सहायता के अलावा, फूड स्ट्रीट पहल में अन्य महत्वपूर्ण पहलें भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगमों और जिला कलेक्टरों को वित्तीय संसाधनों और भौतिक बुनियादी ढांचे को संरेखित करने के प्रयासों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कई गतिविधियां जैसे फूड हैंडलर्स का प्रशिक्षण, स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिट, ईट राइट स्ट्रीट फूड हब का प्रमाणन और फूड स्ट्रीट्स के आधुनिकीकरण के लिए एक मानक प्रोटोकॉल की स्थापना की जाएगी। इन उपायों से फूड स्ट्रीट की सुरक्षा और स्वच्छता मानकों में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, पहल के हिस्से के रूप में, खाद्य संचालकों का प्रशिक्षण, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट, ईट राइट स्ट्रीट

फूड हब का प्रमाणन, और खाद्य सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए एक मानक प्रक्रिया विकसित की जाएगी। यह खाद्य सड़कों की सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को और बढ़ाएगा।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता के रखरखाव और अपशिष्ट निपटान पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर है। इससे रेहड़ी-पटरी वालों को अपने खाद्य कारोबार में सुरक्षित और साफ-सुथरी प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे फूड स्ट्रीट पहल की समग्र सफलता में योगदान मिलेगा।

अभ्यास INIOCHOS-23

INIOCHOS-23 ग्रीस वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहु-राष्ट्रीय वायु अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायु सेना (IAF) भाग लेगी। यह उन तीन अभ्यासों में से एक है जिसमें भारतीय वायु सेना एक साथ भाग लेगी, साथ ही अमेरिका के साथ कलईकुंडा में चल रहे अभ्यास कोप इंडिया और फ्रांस द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास ओरियन, जिसमें चार राफेल लड़ाकू भाग ले रहे हैं। अभ्यास INIOCHOS-23 24 अप्रैल से 4 मई तक ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में आयोजित किया जाएगा।

व्यायाम INIOCHOS-23 का लक्ष्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर-क्षमता को मजबूत करना है। यह अभ्यास विभिन्न देशों को एक साथ आने, अपने ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पेशेवर बातचीत के माध्यम से, भाग लेने वाले दल मूल्यवान आदान-प्रदान में संलग्न हो सकते हैं, जो एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

अभ्यास INIOCHOS-23 एक यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य में आयोजित किया जाएगा जिसमें कई प्रकार की वायु और सतह की संपत्ति शामिल है। यह परिदृश्य भाग लेने वाली वायु सेना को चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी क्षमताओं, रणनीति और रणनीतियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है, और उन्हें अपने कौशल और तकनीकों को परिष्कृत करने में सक्षम बनाता है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यावसायिकता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है।

आईएएफ की भागीदारी

IAF अभ्यास INIOCHOS-23 में चार Su-30 MKI विमान और दो C-17 विमान के साथ भाग लेगा। Su-30 MKI एक अत्याधुनिक मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, गति और चपलता के लिए जाना जाता है। सी-17 विमान एक रणनीतिक एयरलिफ्टर है जो भारी उपकरण, सैनिकों और कार्गो को लंबी दूरी तक ले जा सकता है। अभ्यास इनिओचॉस-23 में इन उन्नत विमानों की भागीदारी अन्य वायु सेना के साथ अपनी परिचालन क्षमताओं और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)

सितंबर 1976 में एक इंडियन एयरलाइंस की उड़ान के अपहरण के बाद जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) में एक सेल के रूप में BCAS की स्थापना की गई थी। सेल की प्राथमिक भूमिका नागरिक उड्डयन सुरक्षा मामलों

पर कर्मियों को प्रबंधित और प्रशिक्षित करना था। अप्रैल 1987 में, जून 1985 में कनिष्क त्रासदी के जवाब में बीसीएएस नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग बन गया।

बीसीएएस की जिम्मेदारियां

बीसीएएस के प्रमुख कर्तव्यों में से एक एयरलाइंस और हवाईअड्डा संचालकों के साथ-साथ एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 के अनुपालन में विमानन सुरक्षा मानकों का निर्माण करना है। बीसीएएस सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है और सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए आकलन करता है। ब्यूरो यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उचित प्रशिक्षण और आवश्यक दक्षता प्राप्त हो।

इसके अलावा, बीसीएएस सुरक्षा कर्मियों की दक्षता और सतर्कता का मूल्यांकन करने के लिए औचक और डमी जांच करने सहित विमानन सुरक्षा मामलों के समन्वय और योजना के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो आकस्मिक योजनाओं की प्रभावशीलता और विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए नकली अभ्यास भी करता है।

37वां स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली में

हाल ही में, BCAS ने नई दिल्ली में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। दो दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनर्स को पुरस्कार प्रदान किए। मंत्री ने बीसीएएस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस 2022 पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और गणतंत्र दिवस 2023 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। सचिव एमओसीए, श्री राजीव बंसल, और महानिदेशक बीसीएएस, श्री जुल्फिकार हसन, भी कार्यक्रम को संबोधित किया, विमानन क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व और विमानन शून्य त्रुटि बनाने में बीसीएएस की भूमिका पर जोर दिया।

सेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 में प्रमुख निर्णय

भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सेना कमांडरों के सम्मेलन (एसीसी) का समापन किया, जो 17-21 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सेना के कमांडरों, सैन्य संचालन महानिदेशक और विभिन्न अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें इन-पर्सन और वर्चुअल दोनों तरह की भागीदारी थी।

सम्मेलन का उद्देश्य सेना की परिचालन तैयारियों और आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा और चर्चा करना था। सम्मेलन के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन-विरोधी उपकरण जैसे बड़ी संख्या में और विशिष्ट तकनीकी-सक्षम उपकरणों की विविधता शामिल है।

कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स (CCOSWs) को सक्रिय करने का निर्णय ग्रे जोन की जरूरतों और साइबर युद्ध क्षमताओं के प्रकटीकरण को ध्यान में रखते हुए सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान किया गया था। यह इकाई भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा कार्यों को पूरा करने में सहायता करेगी। CCOSWs को बढ़ाने का उद्देश्य सेना की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना और नेटवर्क की सुरक्षा करना है।

टीईएस मॉडल परिवर्तन

बी.टेक स्नातकों के रूप में अधिकारियों के प्रवेश के लिए तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) मॉडल में बदलाव आया है। मौजूदा टीईएस मॉडल को पांच साल के मॉडल से चार साल (3+1) मॉडल में बदल दिया गया है, नए टीईएस मॉडल के तहत कैडेट ट्रेनिंग विंग्स (सीटीडब्ल्यू) में तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि तीन साल है। नए टीईएस मॉडल के तहत आईएमए, देहरादून में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण (बीएमटी) आयोजित किया जाएगा।

पैरालंपिक घटनाओं के लिए प्रशिक्षण

नेतृत्व और संगठन सैनिकों की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए, सेना के खेल और मिशन ओलंपिक नोड्स में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके पैरालंपिक खेलों सहित नौ अलग-अलग खेल आयोजनों में कुछ उत्साही सैनिकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य सैनिकों के अपराजेय दृढ़ संकल्प और "कभी हार न मानने" के रवैये का उपयोग करना है।

लीड निदेशालय और टेस्ट बेड फॉर्मेशन

सेना में भविष्य की प्रौद्योगिकियों के बेहतर दोहन की सुविधा के लिए इष्टतम रोजगार दर्शन और स्केलिंग विकसित करने के लिए सेना प्रमुख निदेशालयों और टेस्ट बेड संरचनाओं की स्थापना कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सेना को नवीनतम तकनीकों के साथ बने रहने और अपने विरोधियों से आगे रहने में सक्षम बनाना है।

विश्व विकास रिपोर्ट 2023: प्रवासी, शरणार्थी और समाज

दुनिया की आबादी आठ अरब तक पहुंच गई है और दशकों तक इसके बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कई देशों को कामकाजी उम्र के वयस्कों में तेज गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों और प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर तेज होगी, और कई देश अपनी दीर्घकालिक विकास क्षमता का एहसास करने के लिए प्रवासन पर निर्भर होंगे। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "विश्व विकास रिपोर्ट 2023: प्रवासी, शरणार्थी और समाज" है, गंतव्य, पारगमन और मूल देशों में बेहतर प्रवास प्रबंधन के लिए नीतियों का प्रस्ताव करती है, इसकी तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

मैच-मोटिव फ्रेमवर्क

रिपोर्ट "मैच-मोटिव फ्रेमवर्क" का परिचय देती है, जो एक श्रम अर्थशास्त्र-आधारित दृष्टिकोण है जो इस बात पर जोर देता है कि प्रवासियों के कौशल और गुण गंतव्य देशों की जरूरतों से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। फ्रेमवर्क उन कारणों पर भी विचार करता है कि प्रवासी अवसर की तलाश में क्यों जाते हैं और यह निर्धारित करता है कि प्रवासी, मूल देश और गंतव्य देश प्रवास से किस हद तक लाभान्वित होते हैं। ढांचा मूल, पारगमन, गंतव्य और वैश्विक समुदाय के देशों के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए "मिलान" और "मकसद" को जोड़ता है।

उत्पत्ति और गंतव्य देशों के लिए नीतियां

विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि मूल देशों को श्रम प्रवासन को अपनी विकास रणनीति का एक स्पष्ट हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही, यह सुझाव दिया जाता है कि गंतव्य देश उन क्षेत्रों में प्रवासन को बढ़ावा देते हैं जहां प्रवासी कौशल की अत्यधिक मांग होती है, उन्हें अपने समाज में एकीकृत करने के प्रयास करें, और उन सामाजिक परिणामों से निपटें जो

उनके नागरिकों को चिंतित कर सकते हैं। रिपोर्ट में गंतव्य समाजों की जरूरतों के साथ प्रवासियों के कौशल के मेल को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय प्रयासों का भी आह्वान किया गया है।

जनसंख्या परिवर्तन

कई कम आय वाले देशों को जनसंख्या में वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है, जो उन पर युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दबाव डालेगा। हालाँकि, भारत जैसे विकासशील और गरीब देशों में युवाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि विकसित देश पहले ही इस अवस्था को पार कर चुके हैं, क्योंकि वे जनसंख्याहीनता का अनुभव कर रहे हैं। 47 मिलियन की आबादी वाले स्पेन में 2100 तक एक-तिहाई से अधिक की कमी होने की भविष्यवाणी की गई है, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आबादी का एक बड़ा अनुपात 20 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। चूंकि उनकी आबादी का विस्तार नहीं हो रहा है, मेक्सिको, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और तुर्की जैसे देशों को जल्द ही अधिक विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता हो सकती है।

द बिग कैच-अप -

COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा व्यवधान पैदा किया है, 100 से अधिक देशों में टीकाकरण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप एक संकट पैदा हो गया है, जहां लगभग 75% बच्चे 2021 में रोकथाम योग्य लेकिन गंभीर बीमारियों के खिलाफ आवश्यक टीकाकरण से चूक गए हैं। द बिग कैच-अप नामक एक लक्षित वैश्विक पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ जैसे संगठनों के एक संघ द्वारा लागू किया गया है। , Gavi the Vaccine Alliance, और Immunization Agenda 2030, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के बीच, बच्चों के बीच टीकाकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वे COVID-19 महामारी के कारण गिर गए हैं।

महामारी के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ गया था, जिसके कारण क्लीनिक बंद हो गए थे और शीशियों, सीरिंज और अन्य उपकरणों जैसी चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन में गड़बड़ी पैदा हो गई थी। इसके अलावा, सख्त लॉकडाउन उपाय, यात्रा प्रतिबंध, और घटते वित्तीय और मानव संसाधनों ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को और बढ़ा दिया है। विघटन के कारण पहले से ही खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो और पीला बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप अधिक प्रचलित और गंभीर हो गया है।

प्रगति दिखा रहे देश

जबकि महामारी ने टीकाकरण के प्रयासों को पटरी से उतार दिया है, कुछ देशों ने पहले ही काफी प्रगति दिखाई है। उदाहरण के लिए, भारत 2022 में आवश्यक टीकों में एक मजबूत रिकवरी दर्ज करने में कामयाब रहा, युगांडा महामारी के शुरुआती वर्षों में उच्च टीकाकरण स्तर को बनाए रखते हुए खड़ा हुआ, जबकि केन्या ने देश की उत्तरी खानाबदोश आबादी की टीकाकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दृष्टिकोण को लक्षित किया है।

द बिग कैच-अप

बिग कैच-अप उन 20 देशों पर विशेष ध्यान देगा जहां अधिकांश बच्चे टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं। योजना की मुख्य विशेषताओं में स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करना, विश्वास का

निर्माण करना और समुदायों के भीतर टीकों की मांग, और टीकाकरण को बहाल करने के लिए अंतराल और बाधाओं को दूर करना शामिल है।

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) 2023 के आगामी 6वें संस्करण, जिसे वन अर्थ वन हेल्थ भी कहा जाता है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह आयोजन 26 और 27 अप्रैल को होगा, और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ साझेदारी में, भारत से चिकित्सा सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने और देश को चिकित्सा के नए केंद्र के रूप में पेश करने के लिए AHCI कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) का महत्व:

अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालना

चिकित्सा मूल्य यात्रा, एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत से चिकित्सा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, और यह आयोजन चिकित्सा क्षेत्र में देश की क्षमता को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, सीआईएस, सार्क और आसियान जैसे क्षेत्रों के देशों की भागीदारी के साथ, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा सहयोग के अवसर पैदा करना है। यह कार्यक्रम विदेशी प्रतिभागियों से जुड़ने और संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सह-ब्रांडिंग और शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 (वन अर्थ वन हेल्थ) का छठा संस्करण भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के साथ सह-ब्रांडेड है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल है। शिखर सम्मेलन में 200 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी, चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने और 70+ देशों के 500 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, आर्मेनिया, भूटान, मिस्र, घाना, गिनी, मालदीव, नाइजीरिया, रूस और सोमालिया सहित विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री भाग लेंगे। दस देशों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी, निजी अस्पतालों और चिकित्सा सहायकों के विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (AHCI) का महत्व:

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया (एएचसीआई) इवेंट का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के नए हब के रूप में प्रदर्शित करता है। अपनी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं के साथ, भारत चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है, जो दुनिया भर के रोगियों को आकर्षित करता है। शिखर सम्मेलन भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने और देश की चिकित्सा क्षमता को और बढ़ाने के लिए सहयोग का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों और निर्धारित बी-2-बी बैठकों के माध्यम से 70 से अधिक नामित देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी के साथ, इस आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और इसकी सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की उत्पत्ति और स्थापना

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अवधारणा पहली बार सितंबर 1988 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सदस्य राज्यों के 33वें विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त, 1999 को डब्ल्यूआईपीओ की 30वीं स्थापना वर्षगांठ के साथ स्थापित किया गया था। विश्व आईपी दिवस का उद्घाटन समारोह वर्ष 2000 में हुआ था, जिसमें 59 सदस्य देशों ने भाग लिया था। वर्षों से, इस घटना को मनाने वाले देशों की संख्या धीरे-धीरे 2022 तक बढ़कर 189 हो गई, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता को उजागर करती है।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का उद्देश्य

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बौद्धिक संपदा की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व पर जोर देने और कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और अन्य संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। लोगों को बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और बौद्धिक संपदा अवधारणाओं की समझ को बढ़ावा देने के लिए इस दिन सार्वजनिक आउटरीच अभियान आयोजित किए जाते हैं।

2023 के लिए थीम

महिला रचनाकारों, उद्यमियों और अन्वेषकों को प्रेरित करने के लिए हर साल डब्ल्यूआईपीओ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए एक नई थीम घोषित करता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 के उत्सव का विषय "महिला और आईपी: त्वरित नवाचार और रचनात्मकता" है। इस विषय का उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देना है।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस में रचनाकारों की भूमिका

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के उत्सव में रचनाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिन दुनिया भर के रचनाकारों और उनके संबंधित क्षेत्रों के विकास में उनके योगदान का जश्न मनाता है। यह मूल कार्यों, आविष्कारों और नवाचारों को बनाने में उनके प्रयासों और उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के महत्व को पहचानता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हुए क्रिएटर्स को अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरों को बनाने और नया करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

नवीनतम SIPRI रिपोर्ट

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) एक विश्व प्रसिद्ध थिंक टैंक है जो सुरक्षा मुद्दों के अनुसंधान और विश्लेषण में माहिर है। 1966 में स्थापित, SIPRI शांति, संघर्ष और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र शोध करता है। संस्थान

अपने प्रमुख प्रकाशन, SIPRI ईयरबुक सहित विभिन्न रिपोर्ट और डेटाबेस प्रकाशित करता है। SIPRI द्वारा जारी एक नए डेटा से रक्षा खर्च में वृद्धि का पता चला है।

SIPRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक सैन्य व्यय में साल-दर-साल 3.7% की वृद्धि हुई, जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह 2009 के बाद सबसे बड़ी छलांग है, और कुल खर्च अब 2012 की तुलना में 10% अधिक है।

यूक्रेन स्पर्स के खिलाफ रूस के चौतरफा युद्ध ने सैन्य खर्च में वृद्धि की

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण यूरोपीय देशों द्वारा सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। कई यूरोपीय देश रूस की आक्रामकता के कारण अपने रक्षा बजट पर पुनर्विचार कर रहे हैं और रक्षा क्षमताओं में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। रूस के व्यवहार ने यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं, विशेषकर जो नाटो सदस्य हैं।

नाटो का रक्षा व्यय लक्ष्य

2014 में, नाटो सदस्य 2024 तक रक्षा पर अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहमत हुए। लक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया था कि नाटो के सदस्य सामूहिक रूप से किसी भी संभावित खतरों से बचाव और बचाव कर सकें।

साइबरस्पेस में रूसी खतरा

जबकि रूसी खतरा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साइबर स्पेस में रूस एक शक्तिशाली विरोधी हो सकता है। रूस पर अन्य देशों के बुनियादी ढांचे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की औपनिवेशिक पाइपलाइन के खिलाफ साइबर हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

जीडीपी की तुलना में रक्षा खर्च

2022 में, रक्षा पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 2013 की तुलना में 0.1% कम था। हालांकि, चीन, भारत और इज़राइल जैसे देशों ने पिछले दशक में रक्षा खर्च में दो अंकों की वृद्धि देखी है, हालांकि रक्षा खर्च में वृद्धि नहीं हुई है। उनके राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन का प्रतिशत।

रक्षा खर्च में "अंतराल प्रभाव"

रक्षा खर्च की प्रभावशीलता का आकलन करते समय एक महत्वपूर्ण विचार "अंतराल प्रभाव" है। हथियार प्रणालियों को विकसित करने, खरीदने और उपयोग में लाने में वर्षों लग जाते हैं, जिसका अर्थ है कि बढ़े हुए रक्षा खर्च के प्रभावों को पूरी तरह से महसूस करने में समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय अपना बजट न केवल नए हथियार खरीदने और लड़ाकू बलों के उन्नयन पर खर्च करते हैं, बल्कि कर्मियों, प्रशासन और सैन्य सहायता को नियोजित करने पर भी खर्च करते हैं।

रंग घर

रंग घर भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित एक दो मंजिला इमारत है। इमारत का एक समृद्ध इतिहास है और अहोम राजाओं और रईसों के शासनकाल के दौरान एक शाही खेल मंडप के रूप में कार्य करता था। एम्फीथिएटर असम ट्रंक रोड के किनारे शिवसागर शहर के केंद्र से तीन किलोमीटर दूर स्थित है।

एशिया में एम्फीथिएटर जो समय के साथ जीवित रहने में कामयाब रहे। यह मूल रूप से स्वर्गदेव रुद्र सिंहा के युग के दौरान बनाया गया था, और इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक निर्माण सामग्री बांस और लकड़ी थी। बाद में, स्वर्गदेव प्रमत्त सिंहा ने 1744-1751 ईस्वी के बीच ईंट से संरचना का पुनर्निर्माण किया। रंग घर की अनूठी निर्माण तकनीक और प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताएं असमिया संस्कृति और वास्तुकला की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती हैं।

असम सरकार द्वारा रंग घर के लिए पर्यटक विकास योजना

असम सरकार ने रंग घर के उत्तर-पश्चिम की ओर 26 एकड़ को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित की है। 124 करोड़ की परियोजना में एक कारीगर गांव, गेस्ट हाउस, पर्यटक सूचना केंद्र, एम्फीथिएटर, बोट हाउस और साउंड एंड लाइट शो शामिल हैं। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक परिधानों और स्थानीय व्यंजनों को पर्यटकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

2023 सूडान संघर्ष

सूडान इस साल अप्रैल से अपने सैन्य और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक संघर्ष में घिरा हुआ है। चल रही लड़ाई में कम से कम 420 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई घायल और विस्थापित हुए हैं।

संघर्ष 15 अप्रैल, 2023 को शुरू हुआ, जब सेना और अर्धसैनिक बलों की राजधानी खार्तूम में झड़प हुई। रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागालो की बढ़ती महत्वाकांक्षा से अशांति फैल गई, जिन्होंने सूडान का नेतृत्व करने की मांग की। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान के साथ खड़ा कर दिया, जिससे दोनों के बीच अनबन हो गई।

जंजावीद मिलिशिया

संघर्ष की उत्पत्ति को समझने के लिए जंजावीद मिलिशिया को देखना महत्वपूर्ण है। सूडानी सरकार द्वारा 1980 के दशक की शुरुआत में जंजावेद मिलिशिया को पहली बार सशस्त्र और संगठित किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी गृहयुद्धग्रस्त चाड में सरकार को अपने प्रभाव का विस्तार करने में मदद करना था।

मिलिशिया को 2003 में वैश्विक प्रसिद्धि मिली जब उन पर दारफुर में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। 2003 और 2008 के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप अनुमानित 300,000 मौतें हुईं। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व वाली संयुक्त राज्य सरकार ने 2007 में दारफुर में हुई हिंसा को "नरसंहार" घोषित किया।

जनरल मोहम्मद हमदान डगलो और रैपिड सपोर्ट फोर्स

जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, जिन्हें हेमेटी के नाम से भी जाना जाता है, 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के प्रमुख बने। तब से, आरएसएफ ने सूडान में विशाल सोने के भंडार को खदान करने के लिए रूसी भाड़े के वैगनर समूह के साथ साझेदारी करके अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तार किया है।

70,000 से 150,000 तक के लड़ाकू विमानों की अनुमानित संख्या के साथ, RSF सूडान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूडान का नेतृत्व करने के लिए जनरल मोहम्मद हमदान दगालो (हेमेती) की आकांक्षाओं के साथ आरएसएफ के बढ़ते

प्रभाव और शक्ति ने उनके और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान के बीच एक दरार पैदा कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप चल रहे संघर्ष का परिणाम है।